विचार बिन्दु

सत्ग्रंथ इस लोक की चिंतामणि नहीं उनके अध्ययन से सारी कुचिंताएं मिट जाती है। संशय पिशाच भाग जाते हैं और मन में सद्भाव जागृत होकर परम शांति प्राप्त होती है। –अज्ञात

राजस्थान : परम्परा से प्रगति की ओर

राजस्थान, भारत का वह रंगीन राज्य जो रेगिस्तानों की सुनहरी रेत, किलों की भव्यता और लोक संस्कृति की जीवंतता के लिए जाना जाता है, आज एक अनूठे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यहां की परंपराएं सदियों पुरानी हैं, जो राजपूत शौर्य, भक्ति मार्ग और लोक कला में बसी हुई हैं। लेकिन आधुनिकता की लहर ने इस भूमि को प्रगति के नए क्षितिज प्रदान किए हैं। परंपरा से प्रगति की ओर यह यात्रा न केवल आर्थिक विकास की कहानी है, बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण के साथ नवाचार की मिसाल भी है। राजस्थान ने अपनी जड़ों को मजबूत रखते हुए, सौर ऊर्जा, पर्यटन, आईटी और कृषि क्रांति जैसे क्षेत्रों में छलांग लगाई है। यह आलेख इसी यात्रा को विस्तार से उजागर करता है, जहां थार का रेगिस्तान अब हरित ऊर्जा का केंद्र बन रहा है और जयपुर की हवेलियां डिजिटल स्टार्टअप्स का आश्रय दे रही हैं।

राजस्थान की परंपरागत अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प पर आधारित रही है। यहां के किसान मानसून की बूंदों पर निर्भर रहे, जबकि कारीगरों ने ब्लॉक प्रिंटिंग, बंधेज और मीनाकारी जैसी कला को जीवंत रखा। जयपुर की सियाराम ब्लॉक प्रिंटिंग या बाघोर की थेवा कला आज भी वैश्विक बाजार में राजस्थान की पहचान हैं। लेकिन जल संकट, बेरोजगारी और पारंपरिक बाजारों की सीमाओं ने राज्य को नई दिशा की ओर मोड़ दिया। 1990 के दशक से शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण ने राजस्थान को अवसर प्रदान किए। राज्य सरकार की नीतियां, जैसे राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, ने औद्योगिकरण को गति दी। उदाहरणस्वरूप, निम्स (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) ने चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया, जबकि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) ने अलवर जैसे क्षेत्रों को औद्योगिक हब बना दिया। आज राजस्थान का जीडीपी विकास दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, जो 8-10 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। यह प्रगति परंपरा से कटे बिना हुई है, क्योंकि राज्य ने हेरिटेज होटल नीति के तहत पुरानी हवेलियों को पर्यटन केंद्रों में बदला, जिससे स्थानीय कारीगर लाभान्वित हुए।

पर्यटन राजस्थान की प्रगति का सबसे चमकदार पहलू है। उदयपुर की झीलें, जैसलमेर का सम दुर्ग और जोधपुर का मेहरानगढ़ किला न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, बल्कि राजस्व का प्रमुख स्त्रोत भी हैं। 2025 तक राज्य में 10 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे, जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 50 लाख से ऊपर रही। लेकिन यह परंपरा से प्रगति का संगम है। रिट्ज कार्लटन जैसी चेन ने उदयपुर में हेरिटेज प्रॉपर्टीज विकसित कीं, जबकि पुष्कर फेस्टिवल और डेजर्ट फेस्टिवल लोक नृत्यों को वैश्विक मंच प्रदान करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ने इसे नई ऊंचाई दी। एप्स जैसे राजस्थान टूरिज्म और वर्चुअल रियलिटी टूर्स ने महामारी के दौरान भी पर्यटन को जिंदा रखा। साथ ही, इको-टूरिजम को बढ़ावा मिला है। रणथंभौर और सरिस्का अभयारण्यों में सफारी ने वन्यजीव प्रेमियों को खींचा, जबकि रेगिस्तानी सफारी ने थार को एडवेंचर हब बना दिया। यह विकास सतत है, क्योंकि राज्य ने जीरो वेस्ट टूरिज्म मॉडल अपनाया, जहां प्लास्टिक प्रतिबंध और जैविक सफाई पर जोर है। परिणामस्वरूप, पर्यटन से राज्य को 1.5 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जो स्थानीय रोजगार को दोगुना कर चुका है।

शिक्षा और कौशल विकास में राजस्थान की प्रगति चिंतन का विषय है। परंपरागत रूप से यहां गुरुकुल परंपरा और मदरसों का महत्व रहा, लेकिन आधुनिक शिक्षा ने इसे मजबूत किया। बीकानेर विश्वविद्यालय और जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान अब आईआईटी और आईआईएम स्तर के कोर्स चला रहे हैं। राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया, विशेषकर पर्यटन, आईटी और सौर ऊर्जा में। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर है; बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से साक्षरता दर 70 प्रतिशत से ऊपर पहुंची। उदाहरण के लिए, उदयपुर का आईआईआईटी ने स्टार्टअप इंक्यूबेटर स्थापित किया, जहां छात्र परंपरागत डिजाइन को डिजिटल प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं। लेकिन चुनौतियां बाकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रॉपआउट दर ऊंची है, जिसे ई-लर्निंग से दूर किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया के तहत 50 हजार से अधिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बने, जो राजस्थानी लोककथाओं को डिजिटल कहानियों में बदल रहे हैं। यह परिवर्तन राज्य को मानव संसाधन का मजबूत केंद्र बना रहा है।

आधुनिक तकनीक ने राजस्थान को परिवर्तित कर दिया है। सौर ऊर्जा में राज्य अग्रणी है। भादला सोलर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क, 2.2 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो थार रेगिस्तान की बंजर भूमि को सोने की खान बना रहा है। सौर ऊर्जा नीति 2019 ने 30 गीगावाट लक्ष्य रखा, जो पूरा होने को है। यह न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता ला रहा, बल्कि ग्रामीण रोजगार भी सृजित कर रहा। आईटी सेक्टर में जयपुर सिलिकॉन राजस्थान बन रहा है। महिंद्रा आईटी पार्क और आरएके आईटी पार्क ने 50 हजार नौकरियां पैदा कीं। स्टार्टअप्स जैसे ट्राइवोक (पर्यटन ऐप) और फार्म टू फोर्क (कृषि ई-कॉमर्स) राजस्थानी उद्यमियों की देन हैं।

आधुनिक तकनीक ने राजस्थान को परिवर्तित कर दिया है। सौर ऊर्जा में राज्य अग्रणी है। भादला सोलर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क, 2.2 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो थार रेगिस्तान की बंजर भूमि को सोने की खान बना रहा है। सौर ऊर्जा नीति 2019 ने 30 गीगावाट लक्ष्य रखा, जो पूरा होने को है। यह न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता ला रहा, बल्कि ग्रामीण रोजगार भी सृजित कर रहा। आईटी सेक्टर में जयपुर सिलिकॉन राजस्थान बन रहा है। महिंद्रा आईटी पार्क और आरएके आईटी पार्क ने 50 हजार नौकरियां पैदा कीं। स्टार्टअप्स जैसे ट्राइवोक (पर्यटन ऐप) और फार्म टू फोर्क (कृषि ई-कॉमर्स) राजस्थानी उद्यमियों की देन हैं। डिजिटल इंडिया ने ग्रामीण राजस्थान को जोड़ा; जन आधार कार्ड से 2 करोड़ लोगों को सब्सिडी पहुंची। ई-गवर्नेंस ने भ्रष्टाचार रोका, जैसे भामाशाह योजना ने महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया। लेकिन साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता चुनौतियां हैं, जिन्हें साइबर स्वच्छता केंद्र संबोधित कर रहे हैं।

कृषि और जल प्रबंधन राजस्थान की प्रगति का आधार हैं। परंपरागत खाड़ी और जोहड़ प्रणाली अब आधुनिक सिंचाई से जुड़ रही है। इंदिरा गांधी नहर ने रेगिस्तान को अनाज का कटोरा बना दिया, जिससे गेहूं उत्पादन दोगुना हो गया। मुख्यमंत्री कृषि योजना ने ड्रिप इरिगेशन को सब्सिडी दी, जबकि राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया। बाड़मेर का जीरा और जैसलमेर की बाजरा अब निर्यात हो रहे। डेयरी सेक्टर में अमूल और मदर डेयरी ने सहकारिता को मजबूत किया। जल संरक्षण में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान ने 5 लाख जोहड़ बनाए, जो वर्षा जल संचयन पर आधारित हैं। यह परंपरा (जैसे पंचायत राज जल प्रबंधन) और प्रगति (सेंसर आधारित मॉनिटरिंग) का मेल है। परिणाम? कृषि जीडीपी में 25 प्रतिशत योगदान और किसान आय में 50 प्रतिशत वृद्धि।

सामाजिक परिवर्तन राजस्थान की प्रगति को पूर्णता देते हैं। महिलाओं की सशक्तिकरण में बेटी बचाओ ने लिंगानुपात सुधारा, जबकि उदन जैसी योजनाओं ने स्वरोजगार दिया। आदिवासी क्षेत्रों में एमजीएनआर ने रोजगार सुनिश्चित किया। स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत ने 5 करोड़ कार्ड जारी किए, जबकि कोविड वैक्सीनेशन में राज्य शीर्ष पर रहा। सांस्कृतिक उत्सव जैसे तेजाजी महोत्सव अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे, जो परंपरा को जीवित रखते हैं। लेकिन असमानता बाकी है; शहरी-ग्रामीण खाई को पाटना बाकी है।

राजस्थान की यह यात्रा परंपरा से प्रगति की ओर एक प्रेरणा है। जहां किलों की दीवारें इतिहास सुनाती हैं, वहीं सौर पैनल भविष्य रच रहे हैं। राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया, जहां जीडीपी वृद्धि के साथ पर्यावरण संरक्षण जुड़ा। निवेशक सम्मेलन 2022 ने 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव लाए। भविष्य में मेट्रो विस्तार (जयपुर मेट्रो चरण-2), हाई स्पीड रेल और एयरपोर्ट्स राज्य को कनेक्ट करेंगे। चुनौतियां जैसे जल संकट और बेरोजगारी बनी रहेंगी, लेकिन राजस्थान 2047 विजन उन्हें संबोधित करेगा। यह भूमि सिद्ध करता है कि परंपरा बोझ नहीं, बल्कि प्रगति का आधार है। राजस्थान न केवल विकसित हो रहा, बल्कि अपनी आत्मा को संरक्षित भी कर रहा है।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

भारतीय परिवारों का विखंडन : बाजार, मीडिया और बदलता समाज

सुनील दत्त गोयल

परिवारों का टूटना बाजार के हित में है – यह वाक्य पहली नजर में अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन पिछले तीन दशकों के सामाजिक और आर्थिक आंकड़े इस प्रवृत्ति की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं। जब परिवार बिखरते हैं तो बाजार फलता-फूलता है। पहले एक परिवार एक घर खरीदता या बनवाता था। अब एक से अधिक घर खरीदने पड़ते हैं। एक से अधिक कार, एक से अधिक टेलीविजन, एक से अधिक वाशिंग मशीन और ऐसे ही हर वह वस्तु, जो पहले पूरे परिवार के लिए पर्याप्त हुआ करती थी, अब अलग-अलग घरों के लिए आवश्यक हो गई है।

मैंने यह परिवर्तन लगभग दस वर्ष पहले अपने जीवन में बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया था। मेरे जानकार दो भाइयों ने अलग-अलग मकान लिए। एक बड़ा, संयुक्त परिवार का घर। लेकिन जब परिवार बढ़े, तो बंटवारे की कोई बात न होते हुए भी अलग रहने की आवश्यकता महसूस हुई।

अलग घर लेने का अर्थ सिर्फ दीवारें बदलना नहीं था। सारा सामान दोबारा खरीदा गया – नया टीवी, नया फ्रिज, नया कूलर। यहीं मेरे मन में पहली बार एक प्रश्न उठा। जो नया घर था, वहाँ उस समय की सबसे आधुनिक चीज़ें आईं, जबकि माता-पिता के साथ रहने वाले घर में वही पुराना सामान चलता रहा।

यहीं से एक अदृश्य तुलना शुरू होती है। बच्चों के मन में यह भाव पैदा होता है कि चाचा के घर सब नया है, हमारे घर सब पुराना है। यह कोई बड़ी लड़ाई नहीं होती, लेकिन यही छोटे-छोटे भाव आगे चलकर मानसिक असंतोष और पारिवारिक खटास का कारण बनते हैं। आज यही न्यूक्लियर फैमिली संरचना कई बार रिश्तों के टूटने, यहाँ तक कि तलाक़ तक के कारण बनती दिखाई देती है। अलग रहने से स्वतंत्रता तो बढ़ी है – आने-जाने की, रहने-सहने की, निर्णय लेने की – लेकिन इसी स्वतंत्रता के साथ सामाजिक अनुशासन और पारिवारिक निगरानी भी कम हुई है।

सामाजिक दृष्टि से जो आचरण पहले स्वाभाविक रूप से नियंत्रित रहता था, वह अब खुला हो गया है। उदाहरण के तौर पर, घरों में मांसाहार का बढ़ता प्रयोग, शराब और सिगरेट का सामान्य हो जाना – इन प्रवृत्तियों के पीछे न्यूक्लियर फैमिली में रहना भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि संयुक्त परिवार पूर्णतः दोष-मुक्त थे या न्यूक्लियर परिवार पूर्णतः गलत हैं। लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि न्यूक्लियर परिवार व्यवस्था के कुछ सामाजिक और मानसिक दुष्परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं।

संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर परिवार तकः आंकड़ों की कहानी

भारत की जनगणना (2011) और उसके बाद के राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि संयुक्त परिवारों की संख्या में निरंतर गिरावट आई है और न्यूक्लियर परिवारों की संख्या बढ़ी है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) और विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनों के अनुसार शहरी भारत में एकल या छोटे परिवारों का प्रतिशत 70 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है।

रियल एस्टेट सेक्टर के आंकड़े बताते हैं कि महानगरों में 1 बी एच के और 2 बी एच के फ्लैट्स की मांग पिछले 20 वर्षों में कई गुना बढ़ी है। ऑटोमोबाइल उद्योग की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के सबसे बड़े दोपहिया और प्रमुख चारपहिया बाजारों में शामिल हो चुका है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस सेक्टर की वार्षिक वृद्धि दर 10-15 प्रतिशत के आसपास रही है। यह वृद्धि केवल जनसंख्या वृद्धि से नहीं समझी जा सकती; इसके पीछे परिवार संरचना में परिवर्तन भी एक बड़ा कारण है।

पहले संयुक्त परिवारों में एक ही मिक्सी, एक ही गीजर, एक ही वाशिंग मशीन और सीमित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से काम चल जाता था। आज अलग-अलग घरों में वही सभी वस्तुएं अलग-अलग खरीदी जा रही हैं। परिणामस्वरूप बाजार में बहार आई, लेकिन समाज और परिवार बिखरते चले गए।

सामाजिक सुरक्षा का भारतीय मॉडल

संयुक्त परिवार केवल भावनात्मक व्यवस्था नहीं था, वह भारतीय समाज की वास्तविक सोशल सिक्योरिटी था। यूरोपीय समाजों में जहां पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और वृद्धाश्रम आवश्यक संरचनाएं हैं, भारत में पारिवारिक व्यवस्था ही बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा कवच थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू एच ओ) और भारत के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे (NIMHANS, 2015-16) के अनुसार भारत में हर सात में से एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है। अकेलापन, अवसाद और चिंता विकारों में वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि शहरीकरण, पारिवारिक विखंडन और सामाजिक अलगाव इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं।

पहले संयुक्त परिवारों में पुरुष व्यापार या नौकरी के सिलसिले में बाहर जाते थे, तो घर में बुजुर्ग और अन्य सदस्य परिवार को संभाल लेते थे। महिलाओं को सामाजिक और भावनात्मक सहारा मिलता था। बच्चों का पालन-पोषण सामूहिक रूप से होता था। मनमुटाव होते थे, लेकिन सुलझ भी जाते थे। गली-मोहल्लों की संस्कृति में बच्चे खेलते थे, महिलाएं मिलकर गीत-संगीत करती थीं – आज की भाषा में कहें तो वह किटी पार्टी का सहज, सांस्कृतिक रूप था।

मीडिया और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण

1990 के दशक के बाद उपग्रह चैनलों और मनोरंजन उद्योग के विस्तार ने पारिवारिक छवियों को नए ढंग से प्रस्तुत किया। कई लोकप्रिय धारावाहिकों में संयुक्त परिवार को षड्यंत्र, सास-बहू के झगड़े, अविश्वास और व्यक्तिगत इच्छाओं के दमन के रूप में दिखाया गया। इसके विपरीत न्यूक्लियर परिवार को आधुनिकता, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया।

यह केवल सांस्कृतिक बदलाव नहीं था; यह उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन का भी आधार बना। विज्ञापन उद्योग ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को व्यक्तिगत उपभोग से जोड़ा। अपना घर, अपनी कार, अपनी लाइफस्टाइल – ये स्लोगन केवल भावनात्मक अपील नहीं थे, बल्कि बाजार रणनीति का हिस्सा थे।

शिक्षा, करियर और विलंबित मातृत्व

भारतीय शिक्षण संस्थानों का व्यावसायीकरण भी इस परिवर्तन का एक आयाम है। निजी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों की फीस में पिछले दो दशकों में कई गुना वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस-5) के आंकड़ों के अनुसार कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.0 से नीचे आ चुकी है। शहरी शिक्षित वर्ग में विवाह और मातृत्व की आयु बढ़ी है। नई पीढ़ी करियर, आर्थिक स्थिरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दे रही है। परिणामस्वरूप एक या बिना संतान वाले परिवारों की संख्या बढ़ रही है। इससे रिश्तों का विस्तार – मामा-मामी, चाचा-चाची, ताऊ-ताई, बुआ – फूफा स्वाभाविक रूप से सीमित हो गया है। रिश्तों का संसार अंकल और आंटी तक सिमटता जा रहा है।

डिजिटल युग और अकेलापन

बच्चों के संस्कार अब केवल माता-पिता या दादा-दादी तय नहीं कर रहे; सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंटेंट भी प्रभाव डाल रहे हैं। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 80 करोड़ से अधिक हो चुकी है। औसतन भारतीय युवा प्रतिदिन 4-5 घंटे मोबाइल पर बिताता है।

धीरे-धीरे सुख-दुख के रिश्ते भी समाप्त होने को हैं। बच्चों के संस्कार माता-पिता या दादा-दादी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर तय कर रहे हैं। पहले जो काम दादा-दादी या परिवार के बड़े सदस्य करते थे, वह अब काउंसलर्स करने लगे हैं। बाजार के लिए यह एक आदर्श स्थिति है। हमारी हर समस्या उनके लिए एक प्रोडक्ट है। हमारी हर भावनात्मक आवश्यकता के लिए कोई-न-कोई ऐप है। हर त्यौहार का मतलब है ढेर सारा ऑनलाइन ऑर्डर, चाहे वह सामान काम का हो या न हो। ढेर सारे सब्सक्रिप्शन हमारे पास हैं, जो हर तरह के चाहे-अनचाहे संस्कार हमें बांट रहे हैं। मात्र दो दशक के अंदर हमारा समाज पूरी तरह से बदल गया और यह प्रश्न खड़ा होने लगा कि हम क्या से क्या हो गए। हम कहां से चले और कहां पहुंच गए, और जहां पहुंचे हैं, क्या वहीं पहुँचना जरूरी था या कोई और अच्छा तरीका भी हो सकता था?

उपभोग संस्कृति और त्योहार

त्योहारों का स्वरूप भी बदला है। ई-कॉमर्स कंपनियों की फेस्टिव सेल अरबों रुपये का कारोबार करती हैं। दिवाली, होली या अन्य पर्व अब बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शॉपिंग और ब्रांडेड उपहारों से जुड़ गए हैं। प्रश्न यह है कि क्या यह परिवर्तन अनिवार्य था? क्या दिवाली की खुशी अब केवल ऑनलाइन ऑर्डर से मापी जाएगी? क्या जंक फूड मां के हाथ के खाने से अधिक आकर्षक हो जाएगा? क्या दादी-नानी की कहानियों की जगह नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के वीडियो ले लेंगे?

लैंगिक भूमिकाएं और सामाजिक परिवर्तन

समाज में महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक भागीदारी बढ़ी है, जो सकारात्मक परिवर्तन है। लेकिन इसके साथ जीवनशैली में भी बदलाव आया है। शराब और धूम्रपान जैसे व्यवहार, जो पहले सीमित थे, अब लैंगिक सीमाओं से परे बढ़ रहे हैं। यह परिवर्तन केवल नैतिकता का प्रश्न नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी विषय है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में अल्कोहल उपभोग में वृद्धि दर्ज की गई है। सार्वजनिक विमर्श में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा ने पारिवारिक अनुशासन और सामूहिक जिम्मेदारी के पारंपरिक मॉडल को चुनौती दी है।

आगे का मार्ग

यह आवश्यक नहीं कि संयुक्त परिवार ही एकमात्र आदर्श मॉडल हो। आधुनिक जीवन, शहरी रोजगार और गतिशीलता के अपने व्यावहारिक कारण हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि परिवार के विखंडन के सामाजिक और मानसिक प्रभावों पर गंभीर चर्चा आवश्यक है।

संयुक्त परिवार को बोझ नहीं, संपत्ति के रूप में देखने की आवश्यकता है। बुजुर्गों का सम्मान केवल सांस्कृतिक मूल्य नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता का आधार है। बच्चों को उपभोक्ता नहीं, संस्कारवान नागरिक बनाने की दिशा में प्रयास होना चाहिए। त्योहारों को भावनात्मक और सांस्कृतिक गहराई के साथ मनाना चाहिए, न कि केवल उपभोग के अवसर के रूप में। बाजार जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीवन का केंद्र नहीं होना चाहिए।

आज प्रश्न यह नहीं कि हम आधुनिक क्यों बने; प्रश्न यह है कि क्या आधुनिकता के नाम पर हमने अपनी सामूहिक शक्ति को कमजोर कर दिया? क्या हम आर्थिक प्रगति और पारिवारिक एकता के बीच संतुलन नहीं बना सकते?

यदि हम अभी नहीं रुके, तो अगली पीढ़ी को संयुक्त परिवार का अर्थ समझाना भी कठिन हो जाएगा। समय आ गया है कि हम विकास और मूल्य – दोनों को साथ लेकर चलने की नई सामाजिक रणनीति बनाएं। यही संतुलन भारत की वास्तविक शक्ति रहा है, और भविष्य में भी वही हमारी स्थिरता का आधार बन सकता है।

–रोटेरियन सुनीलदत्त गोयल, एडवाइजर, एडिटर्स क्लब ऑफ़ इंडिया
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

ईरान में जनहित के लिए दूरदर्शी पहल की आवश्यकता

डॉ. नीरज रावत

पश्चिम एशिया का महत्वपूर्ण देश ईरान इस समय एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ लिया गया एक विवेकपूर्ण और साहसिक निर्णय न केवल स्वयं ईरान को व्यापक विनाश से बचा सकता है, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता और शांति की दिशा भी निर्धारित कर सकता है। इतिहास यह स्पष्ट रूप से बताता है कि जब किसी राष्ट्र में संस्थागत संतुलन कमजोर हो जाता है और सत्ता कुछ सीमित संरचनाओं के हाथों में केंद्रित हो जाती है, तो उसका परिणाम अंततः राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव के रूप में सामने आता है। आज ईरान की स्थिति भी कुछ ऐसी ही जटिलताओं से घिरी हुई दिखाई देती है।

ऐसे समय में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम यह हो सकता है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आइआरजीसी) देश के राजनीतिक और सामरिक नियंत्रण से पीछे हटे और ईरान की आधिकारिक राष्ट्रीय सेना को राज्य संचालन की जिम्मेदारी संभालने का अवसर दे। इससे शासन व्यवस्था में आवश्यक संतुलन स्थापित हो सकेगा और राज्य संस्थाएँ अधिक जिम्मेदारी तथा पारदर्शिता के साथ कार्य कर पाएंगी।

ईरान के आधुनिक इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रीय हित में संस्थागत पुनर्संतुलन की आवश्यकता महसूस की जा रही हो। वर्ष 1979 की ईरानी क्रांति के बाद जब शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन समाप्त हुआ, तब देश में एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई। उसी दौर में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य नवगठित इस्लामी व्यवस्था की रक्षा करना था। समय के साथ यह संगठन केवल सुरक्षा तंत्र तक सीमित नहीं रहा और उसने राजनीतिक, आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में भी व्यापक प्रभाव स्थापित कर लिया। परिणामस्वरूप, ईरान की पारंपरिक राष्ट्रीय सेना, जो देश की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए स्थापित की गई थी, अपेक्षाकृत पृष्ठभूमि में चली गई।

ईरान का इतिहास यह भी संकेत देता है कि जब राज्य संस्थाएँ संतुलित और जवाबदेह ढंग से कार्य करती हैं, तब देश अधिक स्थिर और प्रभावी बनता है। बीसवीं सदी की शुरुआत में हुई 1906 की संवैधानिक क्रांति इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस आंदोलन ने ईरान में पहली बार संसद और संवैधानिक शासन की अवधारणा को स्थापित किया। उस समय जनता और बुद्धिजीवियों ने निरंकुश सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए ऐसी व्यवस्था की मांग की थी जिसमें शासन जनता के प्रति जवाबदेह हो और संस्थाओं के बीच संतुलन कायम रहे।

इसी संदर्भ में ईरान की आधिकारिक सेना के प्रमुख की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष यह अपील करनी चाहिए कि ईरान की जनता, उसके शहरों और प्राकृतिक संसाधनों पर हो रहे हमलों को रोका जाए। किसी भी युद्ध या सैन्य टकराव का सबसे अधिक दुष्प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ता है। इतिहास में ईरान-इराक युद्ध (1980-1988) इसका अत्यंत दर्दनाक उदाहरण है। आठ वर्षों तक चले इस संघर्ष ने लाखों लोगों की जान ली और ईरान की अर्थव्यवस्था तथा संसाधनों को भारी क्षति पहुँचाई। इस अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया कि दीर्घकालिक सैन्य संघर्ष अंततः किसी भी देश के लिए लाभकारी नहीं होते।

ऐसी परिस्थितियों में ईरान की राष्ट्रीय सेना के नेतृत्व को एक दूरदर्शी पहल करते हुए यह घोषणा करनी चाहिए कि देश में निकट भविष्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित किए जाएंगे। इन चुनावों के माध्यम से गठित सरकार को देश के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों का संचालन करने का जनादेश प्राप्त होगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनी सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अधिक वैधता और स्वीकार्यता मिलती है, जिससे कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग की संभावनाएँ बढ़ती हैं।

ईरान के इतिहास में जनता की राजनीतिक चेतना हमेशा महत्वपूर्ण रही है। चाहे 1906 की संवैधानिक क्रांति हो, 1950 के दशक में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक के नेतृत्व में तेल के राष्ट्रीयकरण का आंदोलन हो या फिर 1979 की क्रांति हो -- हर दौर में ईरानी जनता ने अपने अधिकारों और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। यह ऐतिहासिक परंपरा बताती है कि यदि जनता को स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जाए, तो वह देश को अधिक स्थिर और संतुलित दिशा में ले जाने की क्षमता रखती है। यदि ईरान इस प्रकार की लोकतांत्रिक और संस्थागत पहल करता है तो उसका प्रभाव केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। इससे पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है और अनावश्यक सैन्य टकराव की संभावनाएँ भी घट सकती हैं। लंबे समय से संघर्ष और अस्थिरता से जूझ रहे इस क्षेत्र के लिए यह एक सकारात्मक और आशाजनक संकेत होगा।

साथ ही, ऐसी पहल से विश्व की लोकतांत्रिक शक्तियाँ भी ईरान की जनता के समर्थन में अधिक मजबूती से खड़ी हो सकेंगी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय सामान्यतः उन देशों के साथ सहयोग बढ़ाता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और जनभागीदारी की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इससे ईरान को आर्थिक, कूटनीतिक और मानवीय सहयोग प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ेगी, जो देश के पुनर्निर्माण और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अंततः किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी जनता और उसकी संस्थाओं की वैधता में निहित होती है। यदि ईरान की संस्थाएँ (विशेषकर उसकी आधिकारिक सेना) इस समय एक जिम्मेदार और दूरदर्शी भूमिका निभाती हैं, तो यह कदम न केवल देश को संभावित विनाश से बचा सकता है, बल्कि उसे एक अधिक स्थिर, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक भविष्य की दिशा में भी अग्रसर कर सकता है। आज आवश्यकता टकराव को बढ़ाने की नहीं, बल्कि ऐसे विवेकपूर्ण निर्णयों की है जो ईरान की जनता और पूरे क्षेत्र के लिए शांति और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त करें।

–डॉ. नीरज रावत,
(अंतरराष्ट्रीय विषयों के जानकार एवं रणनीतिक विशेषज्ञ)

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 13 मार्च, 2026

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 3:03 तक, व्यतिपात योग दिन 10:31 तक, वणिज करण सायं 7:20 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

गृह स्थितिः सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज भद्रा रात्रि 7:20 से आरम्भ होगी। आज दशामाता व्रत, व्यतिपात पुण्य है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर सूर्योदय से 8:11 तक, लाभ-अमृत 8:11 से 11:08 तक, शुभ 12:37 से 2:05 तक, चर 5:02 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:43, सूर्यास्त 6:30

मेष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

वृष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

मिथुन
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**कर्क